विशेषज्ञ की राय

सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए पहला ठोस कदम

अनिल कुमार गुप्ता

सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी (राजस्व परिषद के पूर्व अध्यक्ष)

सरकार ने अपने संतुलित बजट में सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा है। इसे प्रदेश को 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की ओर पहला ठोस कदम कह सकते हैं। इसमें लक्ष्य से जुड़े सभी क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के लिए बजट का प्रावधान किया गया है।

बजट में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की ओर ठोस प्रयास नजर आ रहे हैं। प्रदेश के बजट में केंद्र सरकार के बजट से समन्वय करते हुए प्रावधान किए गए हैं। एमएसएमई के लिए यह बजट काफी अच्छा है। वस्त्रोद्योग से 40 हजार रोजगार सृजन का लक्ष्य भी तय किया गया है। बजट में हाल ही में हुए निवेश सम्मेलन की छाप भी दिखाई देती है। जिन उद्यमियों ने निवेश के लिए करार किए हैं, उन्हें बेहतर सुविधाएं देने का प्रावधान करना जरूरी था। सरकार ने पूर्वांचल व बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे छह स्थानों पर औद्योगिक निर्माण संकुल बनाने का एलान किया है। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और इन क्षेत्रों में भी तेज औद्योगिकीकरण का वातावरण बनेगा।

मेरी नजर में उत्तम से उत्तम बजट की चुनौती समय पर और निर्धारित प्रावधान के तहत खर्च करने की होती है। अगर बजट में प्रस्तावित योजनाओं की प्रगति तय समयसीमा और बजट प्रावधान में होगी तो प्रदेश अपने लक्ष्य की ओर बहुत तेजी से बढ़ेगा।

बजट में सरकार ने अवस्थापना पर भी फोकस किया है। मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे का काम जारी है। झांसी व चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे नए प्रोजेक्ट लिए गए हैं। बुंदेलखंड और पूर्वांचल के विकास पर पहले से ही सरकार फोकस कर रही है। इससे परिवहन व्यवस्था को गति मिलने जा रही है। इसी तरह यूपी की अर्थव्यवस्था अन्य राज्यों के क्रम में बहुत तेजी से बढ़ रही है। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर काफी काम हुआ है। अब गांवों में भी 18-20 घंटे बिजली मिल रही है। नहरों में सिंचाई के लिए पानी है। सरकार पर्यटन पर भी पिछले कुछ वर्षों में तेजी से फोकस कर रही है, जो देशी-विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है।